भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *71
जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2026 को दिया जाना है।
15 माघ, 1947 (शक)

डिजिटल इंडिया योजना का कार्यान्वयन

***71. श्री सनातन पांडेय :**

क्या इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में डिजिटल इंडिया योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या देश भर के सभी गांवों और दूर-दराज के कस्बों को बुनियादी संचार/इंटरनेट सेवाओं से जोड़ दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त सेवाओं से पूरे देश के कब तक जुड़ जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार ऑनलाइन कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए देश के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण युवाओं को शिक्षित करने के लिए सभी गांवों में बुनियादी इंटरनेट सुविधाएं प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

डिजिटल इंडिया योजना का कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 04.02.2026 को लोकसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *71 के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

****

(क) से **(घ):** प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करने और नागरिकों को सशक्त बनाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। इसका समग्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुधार करें, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करें और भारत में निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करें।

इसके मूल में, यह कार्यक्रम तीन परस्पर जुड़े लक्ष्यों को बढ़ावा देता है: डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से वितरित करना और डिजिटल साक्षरता और रोजगार के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना।

कुछ प्रमुख पहलों का विवरण इस प्रकार है:

- **जेएएम ट्रिनिटी** (जन धन-आधार-मोबाइल) भारत सरकार की एक परिवर्तनकारी पहल है जिसे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, शासन व्यवस्था में सुधार करने और कल्याणकारी लाभों और सार्वजनिक सेवाओं की कुशल प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई):** यूपीआई ने देश भर में डिजिटल लेनदेन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। यूपीआई ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लाखों व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को तेज, सुरक्षित और कम लागत वाले डिजिटल भुगतान करने में सशक्त बनाया है, जिससे वित्तीय समावेशन में काफी प्रगति हुई है। यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस, कतर सहित आठ से अधिक देशों में चालू है, जिससे भारत डिजिटल भुगतान के मामले में वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी देश बन गया है। यूपीआई अब दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली है।

    - यूपीआई 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है और 685 बैंकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली बन जाती है।
    - यूपीआई भारत के 81% डिजिटल भुगतान और वैश्विक स्तर पर वास्तविक समय आधार पर डिजिटल भुगतान के लगभग 49% भुगतानों को सशक्त करता है।

- **आधार:** आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है जो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय-आधारित विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करता है। अब तक **143+ करोड़ आधार आईडी** तैयार की जा चुकी हैं।
- **डिजिलॉकर:** डिजिलॉकर ने आम नागरिक के लिए मूल जारीकर्ता से प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक किसी भी समय पहुंच की सुविधा प्रदान की है। डिजिलॉकर की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 65.01 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता इसके साथ पंजीकृत हैं और प्लेटफॉर्म पर 2412 जारीकर्ताओं के माध्यम से 950+ करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी किए गए हैं।
- **उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस)** भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों से कई सरकारी सेवाओं तक सिंगल-विंडो एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान में, 2,390+ (केंद्रीय-872; राजकीय-1518) सेवाएं उमंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेश की जा रही हैं।
- **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम):** जीईएम विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद को सक्षम बनाता है। इसके **1.68 लाख** से अधिक प्राथमिक खरीदार हैं।

- **सामान्य सेवा केंद्र –** सीएससी ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए डिजिटल मोड में सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। **सीएससी के माध्यम से 800** से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) 5.87 लाख सीएससी कार्यरत हैं, जिनमें से 4.57 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर (ग्रामीण क्षेत्रों) पर कार्य कर रहे हैं।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** डीबीटी में कल्याणकारी योजनाओं के तहत सीधे भुगतान करने और नकली लाभार्थियों को हटाने के लिए आधार का उपयोग किया जाता है। अब तक डीबीटी के माध्यम से 48+ लाख करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकांश वितरण डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है।
- **ई-संजीवनी -** ई-संजीवनी आपके स्मार्टफोन से सीधे डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों तक त्वरित और आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म ने देश भर में 44.60 करोड़ से अधिक रोगियों को सेवाएं प्रदान की हैं।
- **माईगव**: माईगव भारत सरकार का एक नागरिक सहभागिता मंच है जिसके माध्यम से नीति निर्माण में लोगों को शामिल करने के लिए कई सरकारी निकायों/मंत्रालयों के साथ सहयोग किया जाता है और सार्वजनिक हित और कल्याणकारी मुद्दों/विषयों पर लोगों की राय मांगी जाती है। वर्तमान में, **6.08+ करोड़ से** अधिक नागरिक माईगव के साथ पंजीकृत हैं, जो माईगव प्लेटफॉर्म पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।
- **जीवन प्रमाण:** जीवन प्रमाण एक आधार बायोमेट्रिक-सक्षम डिजिटल सेवा है जो केंद्रीय, राज्य और अन्य सरकारी पेंशनभोगियों को आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके अपने घरों सहित भारत में कहीं से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) आसानी से प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करती है। 2014 से अब तक इाके माध्यम से 11.96 करोड़ से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रों की प्रक्रिया की जा चुकी है।
- **पीएमजीदिशा:** प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) को देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत देश भर में 6 करोड़ व्यक्तियों की तुलना में, 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल साक्षरता पहलों में से एक उल्लेखनीय पहल बन गई है।
- **फ्यूचरस्किल्स प्राइम:** उद्योग कौशल अंतराल को पाटने के लिए, एमईआईटीवाई ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) के साथ संयुक्त रूप से "फ्यूचरस्किल्स प्राइम" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नई/उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में उम्मीदवारों को फिर से कुशल बनाना है। फ्यूचरस्किल्स प्राइम कार्यक्रम के तहत, प्लेटफॉर्म पर 500+ से अधिक पाठ्यक्रम और 2000+ डिजिटल प्रवाह मार्ग प्रस्तुत किए जाते हैं। 16.20+ लाख उम्मीदवारों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है, जिसमें लगभग 41 प्रतिशत महिला शिक्षार्थी शामिल हैं और टियर-2 और टियर-3 शहरों के 720 उम्मीदवारों ने इनके लिए नामांकन किया है।
- **नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन)** राष्ट्रीय/राज्य डेटा केंद्रों (एनडीसी/एसडीसी), राज्य-व्यापी क्षेत्र नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) के डिजिटल-ट्रैफिक का संचालन करता है और डिजिटल इंडिया की विभिन्न पहलों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है और विभिन्न जी2जी (सरकार से सरकार) और जी2सी (सरकार से नागरिक) सेवाओं, जिला कनेक्टिविटी आदि के डिजिटल-ट्रैफिक को आगे ले जाता है। एनकेएन संसाधन और सहयोगात्मक अनुसंधान साझाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए हाई-स्पीड डेटा संचार नेटवर्क के माध्यम से देश भर के सभी ज्ञान संस्थानों को आपस में जोड़ता है। वर्तमान में, **एनकेएन के तहत 1,869 संस्थागत लिंक** और **एनआईसी जिला केंद्रों के 681 लिंक** चालू हैं, जो देश भर में डिजिटल गवर्नेंस डेटा के सुरक्षित और विश्वसनीय प्रवाह का समर्थन करते हैं।

बुनियादी संचार/इंटरनेट सेवाएं दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के माध्यम से वायरलेस मोबाइल और फिक्स्ड वायरलाइन ब्रॉडबैंड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में इंटरनेट की पहुंच उपलब्ध है। दूरसंचार विभाग (डीओटी), भारत सरकार ने मोबाइल कनेक्टिविटी और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। नवंबर, 2025 की स्थिति के

अनुसार, देश में 123.40+ करोड़ टेलीफोन ग्राहक और 100.30+ करोड़ ब्रॉडबैंड ग्राहक हैं (ट्राई के अनुसार)। प्रमुख परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

- **भारतनेट**: दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार, भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,904 ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा, भारतनेट के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) भी अनुमोदित किया गया है।
- 4जी संतृप्ति परियोजना और अन्य मोबाइल परियोजनाओं के तहत, देश में 23,694 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं ताकि अब तक शामिल न किए गए दूरस्थ क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सके।
- चेन्नई और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (2312 किमी) के बीच 10.08.2020 को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की कमीशनिंग और मुख्य भूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह (कुल 11 द्वीप; कवारत्ती, कल्पेनी, अगत्ती, अमिनी, एंड्रोथ, मिनिकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेतलाट, किल्टन और कदमथ) के बीच 03.01.2024 को सबमरीन ओएफसी कनेक्टिविटी (1869 किमी)। एफटीटीएच और अन्य सेवाओं के प्रावधान के लिए लक्षद्वीप द्वीप समूह में 225 किलोमीटर ओएफसी नेटवर्क का निर्माण किया गया। इन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं ने द्वीपों में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड/इंटरनेट सेवाओं, मोबाइल सेवाओं (4जी/5जी) और अन्य हाई-स्पीड डेटा सेवाओं के तेजी से कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की है।
- भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के अनुसार, **देश के कुल 6,44,131 गांवों** में से **6,34,955 गांवों में** मोबाइल कवरेज है। इसके अलावा, **6,32,058 गांवों** में इंटरनेट कनेक्टिविटी (3जी/4जी मोबाइल कवरेज) है।

*****